



Drishti IAS



करेंट अफेयर्स

उत्तराखण्ड

जून

2024

(संग्रह)

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009

Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501

Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

उत्तराखंड

3

- अतिक्रमण विरोधी अभियान के खिलाफ मजदूरों की रैली 3
- उत्तराखंड में खगोल पर्यटक 3
- मुराड़ी ने गाँव का दर्जा वापस मांगा 4
- वनाग्नि से उत्तराखंड को राहत 5
- तीसरी भारतीय विश्लेषणात्मक कॉन्ग्रेस (IAC) 5
- विश्व पर्यावरण दिवस 6
- सहस्त्र ताल ट्रेक 7
- देहरादून की लीची पर गर्मी का असर 7
- वनाग्नि भारत के लिये चिंता का विषय 8
- भारत गौरव एक्सप्रेस 9
- 'होम ऑफ हिमालयाज' पहल 9
- बिनसर वन्यजीव अभयारण्य 10
- जोशीमठ और कोसियाकुटोली के नाम परिवर्तन 10
- चंपावत को आदर्श ज़िला बनाने की कार्ययोजना 11
- क्राउड आई डिवाइस 12
- खनन निगरानी प्रणाली 13
- विशेष पर्यटक ट्रेन 14
- उत्तराखंड पर्यटन नीति में संशोधन 15
- उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने अवमान नोटिस जारी किया 16
- आदि कैलाश, ओम पर्वत यात्रा स्थगित 17
- खलंगा आरक्षित वन 17
- मानसून के दौरान 13 ग्लेशियल झीलों से उत्पन्न संकट 19

उत्तराखंड

अतिक्रमण विरोधी अभियान के खिलाफ मज़दूरों की रैली

चर्चा में क्यों ?

तिलाड़ी आंदोलन की 92वीं वर्षगांठ मनाने के लिये गांधी पार्क में एक बड़ी सार्वजनिक रैली आयोजित की गई। इसमें दैनिक वेतन भोगी और सामाजिक संगठनों के सदस्य शामिल थे, जो नगर निकायों द्वारा शुरू की गई अतिक्रमण विरोधी गतिविधियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे।

मुख्य बिंदु:

- यह अभियान रिस्पना नदी के बाढ़ के मैदानों से अवैध संरचनाओं को हटाने के लिये राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों के अनुपालन में चलाया जा रहा है।
- नगर निगम आयुक्त द्वारा इस बात पर सहमति जताए जाने के बावजूद कि निवास के प्रमाण के रूप में किसी भी वैध पहचान-पत्र का उपयोग किया जा सकता है, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (MDDA) द्वारा दस्तावेजों को अस्वीकार कर दिया गया था।
- प्रदर्शनकारी ने इन अस्वीकृतियों को चुनौती देने और अपने परिवारों को बेदखल होने से बचाने के लिये दिये गए समय की कमी पर प्रकाश डाला।

तिलाड़ी आंदोलन

- 30 मई, 1930 को टिहरी गढ़वाल राज्य की वन नीति के खिलाफ तिलाड़ी में एक महत्वपूर्ण सत्याग्रह हुआ, जो उत्तराखंड के बाकी हिस्सों में अंग्रेजों द्वारा लागू की गई नीतियों से मिलता-जुलता था।
- जब टिहरी के महाराजा यूरोप में थे, तब उनके प्रधानमंत्री चक्रधर जुयाल ने जलियाँवाला बाग त्रासदी की याद दिलाते हुए तिलाड़ी आंदोलन को क्रूरता से दबा दिया था।
- सैनिकों ने बच्चों सहित निहत्थे लोगों को गोलियों से भून दिया और भागने की कोशिश करते हुए कई लोग यमुना नदी में डूबकर मर गए।

उत्तराखंड में खगोल पर्यटक

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने क्षेत्र में खगोल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये तीन दिवसीय 'नक्षत्र सभा' का आयोजन किया।

- खगोल पर्यटन के अलावा राज्य हरित पर्यटन, साहसिक पर्यटन और स्वास्थ्य पर्यटन पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है।

मुख्य बिंदु:

- यह आयोजन उत्तराखंड में बहुआयामी पर्यटन को बढ़ावा देने की पहल का हिस्सा है।
- इस अग्रणी पहल का उद्देश्य उत्तराखंड को रात्रि आकाश के नीचे असामान्य अनुभव की तलाश करने वाले सितारों और पर्यटकों के लिये एक प्रमुख गंतव्य बनाना है।
- ◆ यह कार्यक्रम मसूरी के जॉर्ज एबरेस्ट शिखर पर आयोजित किया गया, जो बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियों और दून घाटी के शानदार दृश्यों के लिये जाना जाता है।
- इस कार्यक्रम में विशेष उपकरणों के माध्यम से तारों का अवलोकन, विशेषज्ञों द्वारा वार्ता, खगोल फोटोग्राफी प्रतियोगिता और विशेष सौर अवलोकन शामिल थे।

मुराड़ी ने गाँव का दर्जा वापस मांगा

चर्चा में क्यों ?

मुराड़ी को वर्ष 2018 में मुंगरा, नौगाँव और धारी ग्राम पंचायतों के साथ नौगाँव नगर पंचायत में मिला दिया गया था।

- नगर पंचायत का हिस्सा बनने के बाद से गाँव के निवासियों ने लाभ की तुलना में अधिक नुकसान का अनुभव किया है।

मुख्य बिंदु:

- गाँव में कृषि आय का प्राथमिक स्रोत है लेकिन नगर पंचायत में कृषि सुविधाओं का अभाव है।
 - ◆ पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा बनाए गए सिंचाई नहरें (कूल) अब उपेक्षित हैं।
 - ◆ जंगली जानवरों (बंदर, सूअर, आवारा मवेशी) के बढ़ते आक्रमण से फसलों को खतरा है।
- राजमार्ग विस्तार के दौरान क्षतिग्रस्त हुई एक प्रमुख नहर की पाँच वर्षों से मरम्मत नहीं की गई है तथा छोटी नहरें भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जिससे सिंचाई प्रभावित हो रही है।
 - ◆ स्थानीय युवाओं ने अस्थायी नहर मरम्मत के लिये 35,000 रुपए जुटाए, जो सरकारी सहायता के बिना अप्रभावी साबित हुआ।
- ग्राम पंचायत से नगर पंचायत में परिवर्तन के कारण महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS) के लाभ समाप्त हो गए।
- अब निवासियों को सेवा सुधार के बिना उच्च गृह कर, जल एवं विद्युत शुल्क का सामना करना पड़ रहा है।
- मुराड़ी निवासियों की एक प्रमुख चिंता बढ़ता प्रवास है।
 - ◆ इस गाँव में ऐतिहासिक रूप से गैर-प्रवासी समुदाय रहता है, लेकिन निवासियों को डर है कि शहरी समावेशन से यह परंपरा बाधित हो जाएगी।

MGNREGA योजना

- परिचय:
 - ◆ MGNREGA ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2005 में शुरू किये गए विश्व के सबसे बड़े रोजगार गारंटी कार्यक्रमों में से एक है।
 - ◆ यह योजना न्यूनतम वेतन पर सार्वजनिक कार्यों से संबंधित अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम एक सौ दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी प्रदान करता है।
- क्रियान्वित संस्था:
 - ◆ भारत सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय (MRD) राज्य सरकारों के साथ मिलकर इस योजना के संपूर्ण क्रियान्वयन की निगरानी कर रहा है।
- उद्देश्य:
 - ◆ यह अधिनियम ग्रामीण लोगों की क्रय शक्ति में सुधार लाने के उद्देश्य से पेश किया गया था, इसका उद्देश्य मुख्य रूप से ग्रामीण भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को अर्ध या अकुशल कार्य प्रदान करना है।
 - ◆ यह देश में अमीर और गरीब के बीच के अंतर को कम करने का प्रयास करता है।

वनाग्नि से उत्तराखंड को राहत

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में हुई बारिश ने उत्तराखंड के पौड़ी और नैनीताल जैसे इलाकों में लगातार लग रही वनाग्नि से राहत दिलाई है।

मुख्य बिंदु:

- मौजूदा तापमान में दो से तीन डिग्री की गिरावट के बावजूद, निवासियों को सलाह दी जाती है कि वे वनाग्नि को फैलने से रोकने के लिये अपने घरों के आस-पास सूखी झाड़ियों को हटा दें।
- इस मौसम में असामान्य रूप से उच्च तापमान ने वनाग्नि के प्रसार को तेज़ कर दिया है।
- पिछले छह महीनों में, उत्तराखंड में 1,100 से अधिक आग की घटनाएँ हुई हैं, जिसमें 1,500 हेक्टेयर से अधिक वन भूमि नष्ट हो गई है।

वनाग्नि पर सरकारी पहल

- वनाग्नि के लिये राष्ट्रीय कार्य योजना (National Action Plan for Forest Fires- NAPFF) की शुरुआत वर्ष 2018 में वन सीमांत समुदायों को सूचित, सक्षम और सशक्त बनाकर तथा उन्हें राज्य वन विभागों के साथ सहयोग करने के लिये प्रोत्साहित करके वनाग्नि को कम करने के लक्ष्य के साथ की गई थी।
- वनाग्नि निवारण और प्रबंधन योजना (FPM) एकमात्र सरकारी प्रायोजित कार्यक्रम है जो वनाग्नि से निपटने में राज्यों की सहायता करने के लिये समर्पित है।

तीसरी भारतीय विश्लेषणात्मक कॉन्ग्रेस (IAC)

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में उत्तराखंड के देहरादून में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद-भारतीय पेट्रोलियम संस्थान (CSIR-IIP) में तीसरे भारतीय विश्लेषणात्मक कॉन्ग्रेस (IAC) का उद्घाटन किया गया।

- यह तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सह प्रदर्शनी IAC-2024 है। इसका आयोजन CSIR-IIP और इंडियन सोसायटी ऑफ एनालिटिकल साइंटिस्ट (ISAS-दिल्ली चैप्टर) की ओर से संयुक्त रूप से किया जा रहा है।

मुख्य बिंदु:

- सम्मेलन की थीम 'हरित परिवर्तनों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका' है।
- तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन विश्लेषणात्मक विज्ञान में उद्योगों, शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों के लिये इस क्षेत्र में प्रचलित तथा आगामी समाधानों को प्रस्तुत करने के लिये एक मंच प्रदान करेगा।
- ◆ सम्मेलन में पाँच तकनीकी सत्र होंगे, जिनमें प्रख्यात वक्ताओं की वार्ता, शोधकर्ताओं की प्रस्तुतियाँ और विशेष तथा पूर्ण सत्र शामिल होंगे।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR)

- परिचय: वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (Council of Scientific and Industrial Research- CSIR) भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान एवं विकास (R&D) संगठन है। CSIR एक अखिल भारतीय संस्थान है जिसमें 37 राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, 39 दूरस्थ केंद्रों, 3 नवोन्मेषी परिसरों और 5 इकाइयों का एक सक्रिय नेटवर्क शामिल है।
- ◆ CSIR का वित्तपोषण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया जाता है तथा यह सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय के रूप में पंजीकृत है।

◆ CSIR अपने दायरे में रेडियो एवं अंतरिक्ष भौतिकी (Space Physics), समुद्र विज्ञान (Oceanography), भू-भौतिकी (Geophysics), रसायन, ड्रग्स, जीनोमिक्स (Genomics), जैव प्रौद्योगिकी और नैनोटेक्नोलॉजी से लेकर खनन, वैमानिकी (Aeronautics), उपकरण विज्ञान (Instrumentation), पर्यावरण अभियांत्रिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी तक की एक विस्तृत विषय शृंखला को शामिल करता है।

■ यह सामाजिक प्रयासों के संबंध में कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण तकनीकी हस्तक्षेप प्रदान करता है जिसमें पर्यावरण, स्वास्थ्य, पेयजल, भोजन, आवास, ऊर्जा, कृषि-क्षेत्र और गैर-कृषि क्षेत्र शामिल हैं।

● स्थापना: सितंबर 1942

● मुख्यालय: नई दिल्ली

विश्व पर्यावरण दिवस

चर्चा में क्यों ?

पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिये प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है।

मुख्य बिंदु:

- हाल ही में वनों की कटाई/निर्वनीकरण से निपटने के लिये एक उल्लेखनीय पहल करते हुए दो पर्यावरणविदों, जय धर गुप्ता और विजय धस्माना ने उत्तराखंड के राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के भीतर एक टाइगर रिजर्व में भारत का पहला बायोस्फीयर बनाया, जिसे राजाजी राघाटी बायोस्फीयर (RRB) कहा जाता है।
- बायोस्फीयर एक 35 एकड़ की निजी वन पहल है जिसका उद्देश्य क्षेत्र को शिकारियों और खनन से बचाते हुए देशी वृक्षों की दुर्लभ तथा लुप्तप्राय प्रजातियों की पहचान करना एवं उन्हें पुनर्जीवित करना है।
- ◆ RRB के लिये निर्धारित भूमि पहले बंजर और क्षरित अवस्था में थी।
- वे पश्चिमी घाट के साथ महाराष्ट्र के पुणे के पास सह्याद्री टाइगर रिजर्व के बफर जोन में कोयना नदी के ऊपर एक दूसरा बायोस्फीयर भी विकसित कर रहे हैं।

विश्व पर्यावरण दिवस

● परिचय:

- ◆ संयुक्त राष्ट्र सभा ने वर्ष 1972 में विश्व पर्यावरण दिवस की स्थापना की, जो मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम कन्वेंशन का प्रथम दिन था।
- ◆ विश्व पर्यावरण दिवस (WED) प्रतिवर्ष एक विशिष्ट थीम और नारे के साथ मनाया जाता है जो उस समय के प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दों पर केंद्रित होता है।
 - वर्ष 2024 में WED की मेज़बानी सऊदी अरब करेगा।
 - भारत ने वर्ष 2018 में 'प्लास्टिक प्रदूषण को हराएँ' थीम के अंतर्गत विश्व पर्यावरण दिवस के 45वें समारोह की मेज़बानी की।
- ◆ वर्ष 2021 में WED समारोह ने पारिस्थितिकी तंत्र बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक (2021-2030) की शुरुआत की, जो वनों से लेकर खेतों तक, पर्वतों की चोटियों से लेकर सागर की गहराई तक अरबों हेक्टेयर भूमि को पुनर्जीवित करने का एक वैश्विक मिशन है।
- वर्ष 2024 की थीम:
 - ◆ भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता।
 - ◆ वर्ष 2024 मरुस्थलीकरण रोकथाम हेतु संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UN Convention to Combat Desertification- UNCCD) की 30वीं वर्षगांठ भी होगी।

सहस्र ताल ट्रैक

चर्चा में क्यों ?

उत्तराखंड में सहस्र ताल के पास कर्नाटक के नौ ट्रेकर्स की मौत हो गई।

- ये ट्रेकर्स 22 सदस्यीय समूह का हिस्सा थे, जो सहस्र ताल से लौटते समय खराब मौसम के कारण रास्ता भटक जाने से मारे गए।

मुख्य बिंदु:

- राज्य सरकार रेस्क्यू ऑपरेशन टीम के संपर्क में है और मृतकों के परिवारों को सूचित कर दिया गया है।
- सहस्र ताल ट्रैक:
 - यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी ज़िले में 15,000 फुट ऊँचा मार्ग है।
 - यह ट्रैक दोनों तरफ से घिरा हुआ है: पश्चिम में भागीरथी घाटी और पूर्व में भीलंगना घाटी।
 - छोटी झीलों से घिरा कुश कल्याण पठार झील के उत्तर में स्थित है। स्थानीय लोग झील के चारों ओर अपने भगवान को ले जाने की वार्षिक रस्म निभाते हैं क्योंकि उनका मानना है कि यह शुभ होता है।

देहरादून की लीची पर गर्मी का असर

चर्चा में क्यों ?

उत्तराखंड में अत्यधिक गर्मी के कारण, जहाँ तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो गया है, लीची सूख गई है तथा इसके फटने से किसानों को नुकसान पहुँचा है।

मुख्य बिंदु:

- हीट वेव में वृद्धि ने फलों की समग्र वृद्धि और परिपक्वता को प्रभावित किया है
- लीची के पेड़ मृदा से जल अवशोषित करते हैं, जिससे बीज की वृद्धि और बीजाणु के विकास में सहायता मिलती है।
- कंदकोशिका का लाल बाह्य आवरण (छिलके) गर्मी के संपर्क में आने से फट गए हैं, जिससे कंद-कोशिका की लोच में कमी आई है, जिससे फल के रस, आकार और सु-स्वादुता पर असर पड़ा है।
- भौगोलिक संकेत (GI) प्रमाण-पत्र से मान्यता प्राप्त रामनगर लीची की चंडीगढ़, दिल्ली और हरियाणा जैसे आस-पास के राज्यों में काफी मांग है।
- फल-विशेषज्ञों ने लीची की तुड़ाई जल्दी करने के प्रति आगाह किया है, क्योंकि बिहार की लीची उत्तराखंड की लीची से पहले बाजार में आती है।
- चूँकि बिहार की लीची उत्तराखंड की लीची से पहले बिक जाती है, इसलिए फल-विशेषज्ञ/पोमोलॉजिस्ट लीची को जल्दी तोड़ने की सलाह नहीं देते हैं।
 - समय से पहले तोड़ने पर लीचीयाँ खट्टी और छोटी आकार की हो सकती हैं।
 - पेड़ों पर बचे अपरिपक्व लीची के फलों में समुत्थानशीलता बढ़ाने के लिये लीची बागानों में सुबह और शाम पानी देने की सिफारिश की जाती है, साथ ही बोरोन तथा जिबरेलिक एसिड का भी उपयोग किया जाता है।



लीची

- **वानस्पतिक वर्गीकरण:** लीची सैपिंडेसी (Sapindaceae) वर्ग से संबंधित है और अपने स्वादिष्ट, रसीले, पारदर्शी बीज-पत्र अर्थात् खाने योग्य गूदे के लिये जानी जाती है।
- **जलवायु संबंधी आवश्यकताएँ:** लीची उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में पनपती है जिसके लिये नम (आर्द्रता) परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। यह कम ऊँचाई वाले क्षेत्रों में लगभग 800 मीटर की ऊँचाई तक सबसे अच्छी तरह से फलती है।
- **मृदा की प्राथमिकता:** लीची की खेती के लिये आदर्श परिस्थितियों में मिट्टी की भूमिका महत्वपूर्ण है जिसके लिये गहरी, कार्बनिक पदार्थों से भरपूर और अच्छी तरह से सूखी हुई दोमट मिट्टी होनी चाहिये।
- **तापमान संवेदनशीलता:** लीची अत्यधिक तापमान के प्रति संवेदनशील है। यह गर्मियों में 40.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान या सर्दियों में ठंडे तापमान को सहन नहीं कर पाती है।
- **वर्षा प्रभाव:** लंबे समय तक बारिश विशेषकर पुष्प-मंजरी आने के दौरान, परागण की क्रिया में बाधक हो सकती है जो लीची की फसल को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकती है।

वनाग्नि भारत के लिये चिंता का विषय

चर्चा में क्यों ?

अप्रैल से बढ़ते तापमान के कारण उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के वन क्षेत्र जल गए, जिससे संपत्तियों को नुकसान पहुँचा, वन्यजीवों की हानि हुई तथा पर्यटन क्षेत्रों में लंबे समय तक धुआँ रहा।

मुख्य बिंदु:

- **नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (NASA)** के एक्वा और टेरा उपग्रहों पर लगे मॉडरेट रेज़ॉल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रोरेडियोमीटर (MODIS) सेंसर द्वारा एकत्र आँकड़ों के अनुसार, इस सीजन (नवंबर 2023 से जून 2024) में उत्तराखंड वनाग्नि से सबसे ज्यादा प्रभावित होगा।
- ◆ ओडिशा 1,866 आग की घटनाओं के साथ दूसरे स्थान पर रहा, आंध्र प्रदेश 1,788 आग की घटनाओं के साथ तीसरे स्थान पर रहा, महाराष्ट्र में 1,493 तथा छत्तीसगढ़ में वन क्षेत्रों में 1,330 आग की घटनाएँ हुईं।
- उत्तराखंड में, दक्षिण-पश्चिमी भाग में नैनीताल, चंपावत एवं उधम सिंह नगर जिलों में सबसे अधिक और सबसे तीव्र आग की घटनाएँ देखी गईं।
- ◆ उत्तराखंड वन विभाग को आग के कारण 25 लाख रुपए से अधिक के राजस्व का नुकसान हुआ है
- ◆ राज्य सरकार ने जंगलों में चरागाह क्षेत्र में आग लगाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज करने की योजना की घोषणा की है।
- **भारतीय वन सर्वेक्षण** के अनुसार, भारत के 54.4% वन कभी-कभी आग की चपेट में आते हैं, 7.4% में मध्यम स्तर पर आग लगती है तथा 2.4% में आग लगने की घटनाएँ बहुत अधिक होती हैं।

मॉडरेट रेज़ॉल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रोरेडियोमीटर (MODIS)

- मॉडरेट रेज़ॉल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रोरेडियोमीटर, टेरा (मूल रूप से EOS AM-1 के रूप में जाना जाता है) और एक्वा (मूल रूप से EOS PM-1 के रूप में जाना जाता है) उपग्रहों पर लगा एक प्रमुख उपकरण है।
- पृथ्वी के चारों ओर टेरा की कक्षा का समय इस प्रकार निर्धारित है कि यह सुबह के समय भूमध्य रेखा के पार उत्तर से दक्षिण की ओर जाती है, जबकि दोपहर के समय एक्वा भूमध्य रेखा के पार दक्षिण से उत्तर की ओर जाती है।
- टेरा MODIS और एक्वा MODIS प्रत्येक 1 से 2 दिन में संपूर्ण पृथ्वी की सतह का निरीक्षण कर रहे हैं तथा 36 वर्णक्रमीय बैंडों या तरंगदैर्घ्य समूहों में डेटा एकत्र कर रहे हैं।
- ये आँकड़े भूमि, महासागरों और निचले वायुमंडल में होने वाली वैश्विक गतिशीलता तथा प्रक्रियाओं के बारे में हमारी समझ को बेहतर बनाएंगे।
- मॉडरेट रेज़ॉल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रोरेडियोमीटर का प्राथमिक लक्ष्य पृथ्वी पर जलवायु और पर्यावरण के बारे में जानकारी एकत्र करना है, जिसमें विभिन्न वायुमंडलीय, भू-पृष्ठीय तथा महासागरीय मापदंडों का मापन शामिल है।

भारत गौरव एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों ?

भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (IRCTC) ने उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड के सहयोग से तमिलनाडु से उत्तराखंड के छह आध्यात्मिक स्थलों तक चलने वाली भारत गौरव एक्सप्रेस ट्रेन के लिये ऑनलाइन टिकट आरक्षण शुरू किया है।

मुख्य बिंदु:

- छह आध्यात्मिक स्थल हैं: ऋषिकेश, रुद्रप्रयाग, गुप्तकाशी, केदारनाथ, जोशीमठ और बद्रीनाथ।
- ◆ यह यात्रा 13 दिनों की है और इसमें गुप्तकाशी से केदारनाथ तक हेलीकॉप्टर से यात्रा भी शामिल है।
- केदारनाथ धाम रुद्रप्रयाग ज़िले में स्थित है। यह भगवान शिव को समर्पित है और मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। यह भारत में 12 ज्योतिर्लिंगों (भगवान शिव के दिव्य प्रतिनिधित्व) में से एक है।
- रुद्रप्रयाग अलकनंदा नदी के पंच प्रयागों में से एक है, जो अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम स्थल है।
- ◆ इसका नाम भगवान शिव के एक रूप रुद्र के नाम पर रखा गया है। एक पौराणिक कथा के अनुसार, भगवान शिव ने नारद मुनि को आशीर्वाद देने के लिये यहाँ 'रुद्र' के रूप में दर्शन दिये थे।
- जोशीमठ उत्तराखंड के चमोली ज़िले में ऋषिकेश-बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-7) पर स्थित एक पहाड़ी शहर है।
- ◆ यह शहर एक पर्यटक नगर के रूप में कार्य करता है, क्योंकि यह राज्य के अन्य महत्वपूर्ण धार्मिक और पर्यटन स्थलों के अलावा बद्रीनाथ, औली, फूलों की घाटी तथा हेमकुंड साहिब की यात्रा करने वाले लोगों के लिये रात्रि विश्राम स्थल के रूप में कार्य करता है।
- गुप्तकाशी रुद्रप्रयाग ज़िले में स्थित है। यह भगवान शिव को समर्पित अपने प्राचीन विश्वनाथ मंदिर के लिये जाना जाता है जो वाराणसी के मंदिर जैसा ही है।
- ऋषिकेश देहरादून जिले में स्थित है। इसे आमतौर पर 'विश्व की योग राजधानी' कहा जाता है।
- ◆ यह गंगा नदी के दाहिने तट पर स्थित है और हिंदुओं के लिये एक तीर्थस्थल है, जहाँ प्राचीन ऋषि-मुनि उच्च ज्ञान की खोज में ध्यान करते थे।

उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड (Uttarakhand Tourism Development Board- UTDB)

- यह उत्तराखंड राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये जिम्मेदार एक सरकारी निकाय है।
- इसकी स्थापना वर्ष 1976 में हुई थी और इसका मुख्यालय देहरादून में है।
- UTDB पर्यटन बुनियादी ढाँचे को विकसित करने और बढ़ावा देने, निवेश को आकर्षित करने एवं उत्तराखंड को एक पर्यटन स्थल के रूप में बाजार में लाने के लिये कार्य करता है।

'होम ऑफ हिमालयाज' पहल

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड (UTDB) ने सुरम्य आदि कैलाश और ओम पर्वत के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये प्राइम फोकस टेक्नोलॉजीज़ (PFT) के साथ साझेदारी की है। PFT अपनी AI क्षमता और असाधारण मीडिया सेवाओं के लिये प्रसिद्ध है।

- इस साझेदारी का उद्देश्य 'होम ऑफ हिमालयाज' पहल के तहत क्षेत्र के वीडियो बनाना है।

मुख्य बिंदु:

- UTDB और PFT के बीच सहयोग से उत्तराखंड को वैश्विक पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी, जिससे इसके विविध परिदृश्य, समृद्ध विरासत एवं अद्वितीय पर्यटन अनुभव प्रदर्शित होंगे।

- PFT द्वारा शुरू की गई "होम ऑफ हिमालयाज" पहल दो प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है:
 - ◆ उत्तराखंड पर्यटन ब्रांड पहचान को नया स्वरूप देना
 - ◆ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री तैयार करना।
 - ◆ 'होम ऑफ हिमालयाज' पहल वैश्विक मान्यता की ओर उत्तराखंड की यात्रा में एक परिवर्तनकारी उपलब्धि है।

उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड (UTDB)

- यह राज्य में पर्यटन से संबंधित सभी मामलों पर सरकार को सलाह देता है। वैधानिक बोर्ड की अध्यक्षता उत्तराखंड सरकार के पर्यटन मंत्री करते हैं और उत्तराखंड के मुख्य सचिव इसके उपाध्यक्ष हैं।
- पर्यटन के प्रमुख सचिव/सचिव मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। इसमें निजी क्षेत्र से पाँच गैर-सरकारी सदस्य और पर्यटन से संबंधित मामलों के विशेषज्ञ भी होते हैं।

आदि कैलाश और ओम पर्वत

- आदि कैलाश को शिव , छोटा कैलाश, बाबा कैलाश या जोंगलिंगकॉग चोटी के नाम से जाना जाता है, यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित एक पर्वत है।
- ओम पर्वत कैलाश मानसरोवर यात्रा का भी एक हिस्सा है, जिसमें तिब्बत में कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील की यात्रा शामिल है।
- आदि कैलाश और ओम पर्वत के पूजनीय पर्वत उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में भारत-चीन सीमा पर स्थित हैं।
- भगवान शिव के भक्तों के लिये दोनों चोटियाँ धार्मिक महत्त्व रखती हैं।

बिनसर वन्यजीव अभयारण्य

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में अल्मोड़ा जिले के बिनसर वन्यजीव अभयारण्य में लगी भीषण वनाग्नि में टीम के फंस जाने के कारण उत्तराखंड वन विभाग के चार कर्मचारियों की मौत हो गई और चार अन्य घायल हो गए।

मुख्य बिंदु:

- उत्तराखंड में 1 नवंबर, 2023 से 14 जून, 2024 तक 1,213 वनाग्नि की घटनाएँ दर्ज की गई हैं, जबकि वर्ष 2023 में इसी अवधि के दौरान 663 घटनाएँ दर्ज की गई थीं।
- ◆ इस वर्ष वनाग्नि में क्षतिग्रस्त 1653 हेक्टेयर वन भूमि में से गढ़वाल क्षेत्र में 687 हेक्टेयर, कुमाऊँ क्षेत्र में 833 हेक्टेयर और वन्यजीव प्रशासनिक क्षेत्रों में 132 हेक्टेयर भूमि क्षतिग्रस्त हुई है।
- बिनसर वन्यजीव अभयारण्य उत्तराखंड के कुमाऊँ हिमालय में स्थित है।
 - ◆ वर्ष 1988 में इस अभयारण्य की स्थापना क्षेत्र की समृद्ध जैवविविधता के संरक्षण के उद्देश्य से की गई थी।
 - ◆ इसकी विविध स्थलाकृति और ऊँचाई में भिन्नता के कारण यहाँ वनस्पतियों की उल्लेखनीय विविधता है। अभयारण्य मुख्य रूप से ओक तथा देवदार के घने वनों से आच्छादित है
 - ◆ अभयारण्य वन्यजीवों की एक प्रभावशाली श्रृंखला का भी आवास है। अभयारण्य में पक्षियों की 200 से अधिक प्रजातियाँ हैं।
 - इनमें यूरेशियन जय, कोक्लास तीतर, मोनाल तीतर और हिमालयन कठफोड़वा जैसी प्रजातियाँ शामिल हैं।

जोशीमठ और कोसियाकुटोली के नाम परिवर्तन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्र ने उत्तराखंड सरकार के चमोली जिले में जोशीमठ तहसील का नाम बदलकर ज्योतिर्मठ और नैनीताल जिले में कोसियाकुटोली तहसील का नाम बदलकर परगना श्री कैंची धाम तहसील करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी।

- यह कदम इन क्षेत्रों, विशेषकर ऐसे राज्य में जो पहले से ही धार्मिक पर्यटन के लिये एक प्रमुख गंतव्य है, के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्त्व को बढ़ाएगा।

मुख्य बिंदु:

- जोशीमठ वर्ष 2023 में चर्चा में था, जब शहर की कई सड़कों और सैकड़ों इमारतों के ज़मीन में धँसने के कारण बड़ी दरारें पड़ गईं।
- ◆ दूसरी ओर, कोसियाकुटोली तहसील नीम करोली बाबा के कैची धाम आश्रम के लिये प्रसिद्ध है।
- ज्योतिर्मठ (जिसे ज्योतिर पीठ के नाम से भी जाना जाता है) चार प्रमुख मठों में से एक है, जिसके बारे में माना जाता है कि 8वीं शताब्दी के दार्शनिक आदि शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत दर्शन को बढ़ावा देने के लिये पूरे भारत में स्थापित किये थे।
- ◆ ज्योतिर्मठ की स्थापना आध्यात्मिक ज्ञान और प्रथाओं के संरक्षण एवं प्रसार के लिये की गई थी।
- ज्योतिर्मठ इस पहाड़ी शहर का प्राचीन नाम था। समय के साथ, स्थानीय आबादी ने इस क्षेत्र को "जोशीमठ" कहना शुरू कर दिया। यह परिवर्तन संभवतः क्रमिक और स्वाभाविक था, जो क्षेत्रीय भाषाओं, स्थानीय बोलियों एवं उच्चारण की सहजता से प्रभावित था। यह परिवर्तन किसी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना के बजाय भाषायी और सांस्कृतिक विकास को दर्शाता है।
- हाल के वर्षों में कुछ निवासियों ने शहर के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्त्व को सम्मान देने के लिये नाम में बदलाव की मांग की है।
- ◆ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्ष 2023 में चमोली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान बदलाव की घोषणा की।
- जोशीमठ जहाँ पुराने नाम से एक सूक्ष्म परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है, वहीं कोसियाकुटोली का मामला एक कम-ज्ञात नाम को बदलने के संदर्भ में है जिसे व्यापक मान्यता नहीं मिली है।
- ◆ इसका नाम बदलकर परगना श्री कैची धाम करने से इसकी पहचान नीम करोली बाबा के कैची धाम आश्रम से जुड़ जाती है, जो यहाँ का एक प्रमुख स्थल है जो विश्व भर से भक्तों को आकर्षित करता है।
- "कोसियाकुटोली" नाम में "कोसी" उसी नाम की नदी को संदर्भित करता है जो नैनीताल ज़िले से होकर बहती है और उत्तराखंड के कुमाऊँ क्षेत्र के लिये महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ाने के साथ-साथ यह स्थानीय पारिस्थितिकी और अर्थव्यवस्था के लिये भी महत्वपूर्ण है। "कुटोली" शब्द स्थानीय भाषा से लिया गया है, जो किसी गाँव या बस्ती को संदर्भित करता है। कुमाऊँनी भाषा में नदी जैसी प्रमुख भौगोलिक विशेषता के नाम पर किसी स्थान का नाम रखना आम बात है और नामों का अर्थ प्रायः परिदृश्य, स्थानीय इतिहास या सांस्कृतिक विशेषताओं से जुड़ा होता है।

चंपावत को आदर्श ज़िला बनाने की कार्ययोजना**चर्चा में क्यों ?**

हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में चंपावत ज़िले को आदर्श ज़िला बनाने की कार्ययोजना और चल रहे कार्यों की समीक्षा की।

- उत्तराखंड को आदर्श राज्य बनाने के लिये चंपावत ज़िले को आदर्श ज़िले के रूप में लिया जा रहा है।

मुख्य बिंदु:

- चंपावत में मैदानी, तराई, भाबर और पहाड़ी क्षेत्रों सहित विविध भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं।
- मुख्यमंत्री ने विकास और विरासत दोनों को आगे बढ़ाने के महत्त्व पर जोर देते हुए अधिकारियों से आदर्श जनपद चंपावत के लिये कार्ययोजना को तेजी से लागू करने का आग्रह किया।
- उन्होंने अधिकारियों को पारिस्थितिकी और पर्यावरण संबंधी चिंताओं के साथ विकास कार्यों का समन्वय करने का भी निर्देश दिया। साथ ही प्राकृतिक विरासत के संरक्षण को विकास प्रयासों में एकीकृत किये जाने की बात कही।
- चंपावत ज़िला धार्मिक, आध्यात्मिक और साहसिक पर्यटन के लिये कई अवसर प्रदान करता है।
- ज़िले में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये तीन से चार दिवसीय यात्रा सर्किट बनाना महत्वपूर्ण है।

- पूर्णागिरी मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, इसलिये उनकी सुविधा सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक व्यवस्था करना महत्वपूर्ण है।
- चंपावत जिले में पर्यटन, कृषि, बागवानी, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, दूध और इससे जुड़े उत्पादों को बढ़ावा देने के लिये कार्ययोजना बनाई जा रही है। इसका लक्ष्य चंपावत को आदर्श राज्य बनाना है, जिसके लिये वर्ष 2030 तक की योजनाएँ बनाई जा रही हैं।
- चंपावत जिले के प्रत्येक पात्र व्यक्ति को केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिये प्रयास किये जा रहे हैं।
- सौर ऊर्जा में संभावनाओं को तलाशने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही, टाउन प्लानिंग पर विशेष ध्यान देकर ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर बढ़ते पलायन को रोकने पर भी ध्यान दिया जा रहा है।

पूर्णागिरी मंदिर

- पूर्णागिरी को पुण्यगिरी के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर शारदा नदी के पास स्थित है। पूर्णागिरी मंदिर अपने चमत्कारों के लिये भी जाना जाता है
- माँ पूर्णागिरी मंदिर उत्तराखंड के चंपावत जिले के टनकपुर के पर्वतीय क्षेत्र में अन्नपूर्णा छोटी की चोटी पर लगभग 3000 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है
- मंदिर को शक्तिपीठ माना जाता है और यह 108 सिद्धपीठों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि इस स्थान पर माता सती की नाभि गिरी थी।

क्राउड आई डिवाइस

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) रुड़की ने चार धाम तीर्थयात्रियों की बढ़ती संख्या को नियंत्रित करने के लिये 'क्राउड आई' डिवाइस विकसित की है, जो भीड़ बढ़ने से पहले अलर्ट भेजती है।

- प्रायोगिक तौर पर यमुनोत्री में पहली क्राउड आई डिवाइस लगाने की तैयारी की जा रही है।

मुख्य बिंदु:

- यह उपकरण धार्मिक स्थलों पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिये वास्तविक समय पर निगरानी रखने हेतु बनाया गया है।
- यमुनोत्री में स्थानीय स्तर पर विकसित 'क्राउड आई' उपकरण स्थापित करने के लिये देहरादून स्थित उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (UCOST) को वित्त पोषण हेतु अनुरोध प्रस्तुत किया गया है।
- बजट स्वीकृति के बाद यह परियोजना शुरू होगी, जिसकी उत्पादन लागत 60 से 70 हजार रुपए अनुमानित है। इस तकनीक को पेटेंट कराने के भी प्रयास किये जा रहे हैं।
- भावी अपडेट का उद्देश्य भीड़ की गणना में पुरुष और महिला डेटा के बीच अंतर करना है।
- हरिद्वार में दीनदयाल उपाध्याय और पंतद्वीप पार्किंग क्षेत्रों में सर्वेक्षण के माध्यम से तीर्थयात्रा सीजन के दौरान यातायात की भीड़ की समस्या का समाधान किया जा रहा है।

चार धाम यात्रा

- यमुनोत्री धाम:
 - ◆ स्थान: उत्तरकाशी जिला।
 - ◆ समर्पित: देवी यमुना।
 - ◆ गंगा नदी के बाद यमुना नदी भारत की दूसरी सबसे पवित्र नदी है।

- गंगोत्री धाम:
 - ◆ स्थान: उत्तरकाशी जिला।
 - ◆ समर्पित: देवी गंगा।
 - ◆ सभी भारतीय नदियों में सबसे पवित्र मानी जाती है।
- केदारनाथ धाम:
 - ◆ स्थान: रुद्रप्रयाग जिला।
 - ◆ समर्पित: भगवान शिव।
 - ◆ मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है।
 - ◆ भारत में 12 ज्योतिर्लिंगों (भगवान शिव के दिव्य प्रतिनिधित्व) में से एक।
- बद्रीनाथ धाम:
 - ◆ स्थान: चमोली जिला।
 - ◆ पवित्र बद्रीनारायण मंदिर का स्थान।
 - ◆ समर्पित: भगवान विष्णु
 - ◆ वैष्णवों के पवित्र तीर्थस्थलों में से एक।

खनन निगरानी प्रणाली

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिये राज्य में **खनन डिजिटल परिवर्तन और निगरानी प्रणाली (MDTSS)** की स्थापना हेतु 93 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को स्वीकृति दी।

मुख्य बिंदु:

- देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर में 40 चेक गेटों पर ये सिस्टम लगाए जाएंगे।
- बुलेट कैमरा, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) रडार और लाइट एमिटिंग डायोड (LED) फ्लडलाइट से लैस नई प्रणाली न केवल अवैध खनन गतिविधियों की निगरानी करने में मदद करेगी बल्कि राज्य सरकार के राजस्व को भी बढ़ाएगी।
- देहरादून में **खनन राज्य नियंत्रण केंद्र (MSCC)** स्थापित किया जाएगा, साथ ही देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर में जिला मुख्यालयों पर मिनी कमांड सेंटर भी स्थापित किये जाएंगे।

अवैध खनन

- परिचय:
 - ◆ अवैध खनन में सरकारी अधिकारियों से **आवश्यक परमिट, लाइसेंस या विनियामक अनुमोदन के बिना** भूमि या जल निकायों से खनिजों, अयस्कों या अन्य मूल्यवान संसाधनों का निष्कर्षण शामिल है।
 - ◆ इसमें पर्यावरण, श्रम और सुरक्षा मानकों का उल्लंघन भी शामिल हो सकता है।
- मुद्दे:
 - ◆ **पर्यावरणीय क्षरण:**
 - इससे निर्वनीकरण, मृदा अपरदन और जल प्रदूषण हो सकता है तथा इसके परिणामस्वरूप **वन्यजीवों के आवास नष्ट हो सकते हैं**, जिसके गंभीर पारिस्थितिक परिणाम हो सकते हैं।

◆ खतरे:

- अवैध खनन में प्रायः **पारा** और **साइनाइड** जैसे खतरनाक रसायनों का प्रयोग शामिल होता है, जो खनिकों तथा आस-पास के समुदायों के लिये गंभीर स्वास्थ्य जोखिम उत्पन्न कर सकते हैं।

◆ राजस्व की हानि:

- इससे सरकारों को राजस्व की हानि हो सकती है क्योंकि खनिक उचित कर और रॉयल्टी का भुगतान नहीं कर सकते हैं।
- इसका महत्वपूर्ण आर्थिक प्रभाव हो सकता है, विशेषकर उन देशों में जहाँ प्राकृतिक संसाधन राजस्व का एक प्रमुख स्रोत हैं।

◆ मानवाधिकार उल्लंघन:

- अवैध खनन के परिणामस्वरूप **मानवाधिकार उल्लंघन** भी हो सकता है, जिसमें जबरन श्रम, बाल श्रम और कमजोर आबादी का शोषण शामिल है।

रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (Radio Frequency Identification- RFID

- रडार RFID एक प्रकार की निष्क्रिय वायरलेस तकनीक है जो किसी वस्तु या व्यक्ति को ट्रैक करने की अनुमति देती है।
- इस प्रणाली के दो आधारभूत भाग हैं: टैग और रीडर।
- ◆ रीडर रेडियो तरंगें उत्पन्न करता है और RFID टैग से सिग्नल वापस प्राप्त करता है, जबकि टैग अपनी पहचान तथा अन्य जानकारी संप्रेषित करने के लिये रेडियो तरंगों का प्रयोग करता है।
- ◆ टैग को कई फीट दूर से पढ़ा जा सकता है और ट्रैक किये जाने के लिये रीडर के सरल रेखिक होने की आवश्यकता नहीं है।
- इस तकनीक को 1970 के दशक से पूर्व से ही स्वीकृति दी गई है, लेकिन वैश्विक आपूर्ति शृंखला प्रबंधन और पालतू माइक्रोचिपिंग जैसी चीजों में इसके प्रयोग के कारण हाल के वर्षों में यह बहुत अधिक प्रचलित हो गई है।

विशेष पर्यटक ट्रेन

चर्चा में क्यों ?

सूत्रों के अनुसार, **उत्तराखंड पर्यटन विभाग** ने दक्षिण भारत में एक समर्पित पर्यटक ट्रेन संचालित करने के लिये **भारतीय रेलवे खान-पान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड (IRCTC)** के साथ साझेदारी की है।

मुख्य बिंदु:

- केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत **केदार ब्रह्मी कार्तिक (मुरुगन) कोइल यथिराई** नामक अनूठी ट्रेन तमिलनाडु के मदुरै से ऋषिकेश तक 165 यात्रियों के साथ अपनी पहली यात्रा शुरू करेगी।
- ट्रेन में सवार सभी 165 यात्रियों को 12 दिन और रात के लिये विशेष टूर पैकेज दिये गए हैं।
 - ◆ इसमें **रुद्रप्रयाग, बद्रिनाथ** और **केदारनाथ** में नए खोजे गए पर्यटक स्थल **कार्तिक स्वामी मंदिर** के दर्शन शामिल हैं।
 - ◆ टूर पैकेज में पर्यटकों के लिये विश्राम और खाने-पीने की पूरी सुविधा शामिल है।
- उत्तराखंड पर्यटन का उद्देश्य दक्षिण, विशेषकर चेन्नई से अधिक तीर्थयात्रियों को आकर्षित करना है, ताकि उन्हें रुद्रप्रयाग जिले में एक नए विकसित महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल कार्तिक स्वामी मंदिर से जोड़ा जा सके।
 - ◆ मान्यता के अनुसार शिव के पुत्र **भगवान कार्तिकेय** अपने माता-पिता के साथ यहाँ आए थे और उन्होंने अपनी **अस्थियाँ पिता को तथा देह/आमिष माता को सौंप दिया** था।
 - ◆ ऐसा कहा जाता है कि ये अस्थियाँ मंदिर में मौजूद हैं। उत्तर भारत में यह **भगवान कार्तिकेय** का एकमात्र मंदिर है, जिन्हें दक्षिण भारत में देवता मुरुगन के रूप में जाना जाता है।

- उत्तराखंड पर्यटन विभाग ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों, विशेष रूप से पश्चिमी और दक्षिण भारत से विशेष रेलगाड़ियाँ संचालित करने के लिये IRCTC के साथ सहयोग किया है।
- ◆ महाराष्ट्र और पश्चिम के अन्य राज्यों से पर्यटकों को कुमाऊँ क्षेत्रों की ओर आकर्षित करने के लिये मार्च तथा अप्रैल, 2024 में पुणे से मानसखंड एक्सप्रेस नामक दो विशेष रेलगाड़ियाँ शुरू की गईं।

भारतीय रेलवे खान-पान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड (Indian Railway Catering and Tourism Corporation- IRCTC)

- यह एक मिनी रत्न श्रेणी-I (वर्ष 2008 में प्रदान किया गया) केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है जो पूरी तरह से रेल मंत्रालय के स्वामित्व में है और उसके प्रशासनिक नियंत्रण में है।
- यह एक पंजीकृत उद्यम है और इसका कॉर्पोरेट कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है।
- IRCTC को सितंबर 1999 में भारतीय रेलवे की विस्तारित शाखा के रूप में शामिल किया गया था, जिसका उद्देश्य स्टेशनों, ट्रेनों और अन्य स्थानों पर खान-पान तथा आतिथ्य सेवाओं को उन्नत, पेशेवर बनाना एवं इनका प्रबंधन करना है। यह फर्म वर्तमान में 4 व्यावसायिक क्षेत्रों में काम करती है, अर्थात् इंटरनेट टिकटिंग, खान-पान, पैकेजिंग पेयजल, यात्रा और पर्यटन। यह एकमात्र इकाई है जिसे भारतीय रेलवे द्वारा देश में रेलवे स्टेशनों तथा ट्रेनों में खान-पान सेवाएँ, ऑनलाइन रेलवे टिकट एवं पैकेज्ड पेयजल प्रदान करने के लिये अधिकृत किया गया है।
- ◆ इससे ई-टिकटिंग, पैकेज्ड पेयजल और ई-कैटरिंग में बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने में इसका लाभ मिलता है।

उत्तराखंड पर्यटन नीति में संशोधन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने राज्य की पर्यटन नीति- 2018 में संशोधन को मंजूरी दी, जिसमें विभिन्न उद्योगों को राज्य वस्तु एवं सेवा कर (SGST) मुआवजा मिलने की अवधि निर्दिष्ट की गई।

मुख्य बिंदु:

- संशोधन के अनुसार, उत्तराखंड में A, B और B+ श्रेणी के उद्योगों को पाँच वर्ष के लिये 100% SGST मुआवजा मिलेगा, जिसके बाद उन्हें अगले पाँच वर्षों के लिये क्रमशः 90, 75 तथा 75% की दर से यह मिलेगा।
- ◆ लार्ज, मेगा और अल्ट्रा-मेगा परियोजनाओं को 10 वर्षों के लिये क्रमशः 30 तथा 50% का SGST मुआवजा मिलेगा।
- उत्तराखंड पर्यटन नीति- 2018 का उद्देश्य इस क्षेत्र में निवेशकों के लिये एकल-खिड़की निकासी प्रणाली स्थापित करना था।
- ◆ हालाँकि राज्य में विभिन्न उद्योगों को SGST मुआवजा प्रदान करने की अवधि निर्दिष्ट नहीं की गई थी।
- राज्य मंत्रिमंडल ने यह भी निर्णय लिया:
 - ◆ विशेषज्ञ डॉक्टरों की सेवा अवधि को 65 वर्ष की आयु तक बढ़ाया जाए।
 - ◆ शहरी परिवहन व्यवस्था के विकास, संचालन और निर्वहन के लिये राज्य विधानसभा में एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण विधेयक, 2024 पेश किया जाए
 - ◆ सहकारी समिति के नियमों में संशोधन कर इसकी प्रबंधन समितियों में 33% पद महिलाओं के लिये आरक्षित किया जाए।
 - ◆ महासू देवता मंदिर के आस-पास रहने वाले परिवारों को पुनर्स्थापित करें।

महासू देवता मंदिर

- यह उत्तराखंड के देहरादून जिले के हनोल में त्यूनी-मोरी मार्ग पर स्थित है और 9वीं शताब्दी में बनाया गया था।
- यह मंदिर महासू देवता को समर्पित है। इसका निर्माण काठ-कुनी या कोटि-बनाल वास्तुकला शैली में किया गया था।
- यह भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण की उत्तराखंड के देहरादून सर्कल के प्राचीन मंदिरों की सूची में शामिल है।

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने अवमान नोटिस जारी किया

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने 10 वर्ष की सेवा वाले व्याख्याताओं और सहायक अध्यापकों को उच्च वेतनमान प्रदान करने के अपने आदेशों का पालन न करने पर विद्यालयी शिक्षा निदेशक को अवमान नोटिस जारी किया है।

मुख्य बिंदु:

- पिछले आदेश के अनुसार, उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था कि व्याख्याताओं और सहायक अध्यापकों को चयन तथा पदोन्नति वेतनमान के साथ अतिरिक्त वेतन वृद्धि मिलनी चाहिये।
- ◆ सरकार अभी भी इस मुद्दे पर विचार-विमर्श कर रही है और अंतिम निर्णय पर नहीं पहुँची है।
- वर्ष 2011 में नियुक्त व्याख्याताओं ने तर्क दिया कि उन्हें दस वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद उत्तराखंड सरकारी सेवक वेतन नियम, 2016 के अनुसार अतिरिक्त वेतन वृद्धि तथा चयन वेतनमान मिलना चाहिये।
- ◆ सरकार ने एक दशक बाद चयन वेतनमान तो दिया, लेकिन उम्मीद के मुताबिक अतिरिक्त वेतन वृद्धि नहीं दी।

न्यायालय अवमान

- परिचय:
 - ◆ न्यायालय अवमान न्यायिक संस्थाओं को प्रेरित हमलों और अनुचित आलोचना से बचाने तथा इसके अधिकार को कम करने वालों को दंडित करने के लिये एक वैधानिक तंत्र के रूप में कार्य करती है।
- वैधानिक आधार:
 - ◆ जब संविधान को अपनाया गया था, तब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 (2) के तहत न्यायालय अवमान को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों में से एक बनाया गया था।
 - ◆ इसके अलावा, संविधान के अनुच्छेद 129 ने सर्वोच्च न्यायालय को स्वयं के अवमान को दंडित करने की शक्ति प्रदान की। अनुच्छेद 215 ने उच्च न्यायालयों को इसी प्रकार की शक्ति प्रदान की।
 - ◆ न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 इस विचार को वैधानिक समर्थन देता है।
- न्यायालय अवमान के प्रकार:
 - ◆ सिविल अवमान: यह न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री, निर्देश, आदेश, रिट या अन्य प्रक्रिया की जानबूझकर अवज्ञा या न्यायालय को दिये गए वचन का जानबूझकर उल्लंघन है।
 - ◆ आपराधिक अवमान: यह किसी भी मामले का प्रकाशन या व: अन्य कार्य है जो किसी भी न्यायालय के अधिकार को कम करता है या इसको बदनाम करता है अथवा किसी न्यायिक कार्यवाही के नियत क्रम में हस्तक्षेप करता है अथवा किसी अन्य तरीके से न्याय प्रशासन को बाधित करता है।
- सजा:
 - ◆ न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 के तहत दोषी को छह महीने तक की कैद या 2,000 रुपए का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।
 - इसमें वर्ष 2006 में संशोधन करके बचाव के तौर पर “सत्य और सद्भावना” को शामिल किया गया।
 - इसमें यह भी जोड़ा गया कि न्यायालय केवल तभी दंड दे सकता है जब दूसरे व्यक्ति का कार्य न्याय के उचित तरीके में बहुत हद तक हस्तक्षेप करता हो या हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति रखता हो।

आदि कैलाश, ओम पर्वत यात्रा स्थगित

चर्चा में क्यों ?

अधिकारियों के अनुसार, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में **आदि कैलाश और ओम पर्वत** की तीर्थयात्रा 25 जून, 2024 से अस्थायी रूप से निलंबित कर दी जाएगी।

मुख्य बिंदु:

मानसून के कारण उच्च ऊँचाई वाले स्थलों की तीर्थयात्रा में व्यवधान उत्पन्न होने की आशंका के कारण यात्रा को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया था। यात्रा की बुकिंग पुनः सितंबर 2024 में प्रारंभ की जाएगी।

आदि कैलाश और ओम पर्वत



- आदि कैलाश को शिव , छोटा कैलाश, बाबा कैलाश या **जोंगलिंगकॉंग चोटी** के नाम से जाना जाता है, यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में **हिमालय पर्वत श्रृंखला** में स्थित एक पर्वत है।
- ओम पर्वत **कैलाश मानसरोवर यात्रा** का भी एक हिस्सा है, जिसमें तिब्बत में कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील की यात्रा शामिल है।
- आदि कैलाश और ओम पर्वत के पूजनीय पर्वत उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में **भारत-चीन सीमा** पर स्थित हैं।
- भगवान शिव के भक्तों के लिये दोनों चोटियाँ धार्मिक महत्त्व रखती हैं।

खलंगा आरक्षित वन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में देहरादून के स्थानीय निवासी **खलंगा आरक्षित वन** में 2,000 साल **वृक्षों** को बचाने के लिये एकजुट हुए। वृक्षों की कटाई के खिलाफ जनता के विरोध के कारण, राज्य सरकार नियोजित पेयजल संयंत्र को जंगल से स्थानांतरित करेगी।

मुख्य बिंदु:

- पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने **सोंग बाँध पेयजल परियोजना** के लिये खलंगा आरक्षित वन में 2000 साल वृक्षों को चिह्नित करने का **विरोध किया**, जिससे स्थानीय लोगों में गहरी नाराजगी उत्पन्न हो गई और उन्होंने परियोजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया।
- जागरूकता फैलाने के लिये सोशल मीडिया पर **अभियान चलाया गया** और कुछ समूहों ने वृक्षों पर रक्षासूत्र बाँधे।
- देहरादून में **सोंग बाँध परियोजना** के अंतर्गत 524 करोड़ रुपए की पेयजल परियोजना बनाई जाएगी, जिसकी अनुमानित कुल लागत 3000 करोड़ रुपए है।
- ◆ इस परियोजना में सोंग बाँध के निकट एक जलाशय का निर्माण तथा 4.2 हेक्टेयर भूमि पर 150 MLD (मेगालिटर प्रतिदिन) जल उपचार संयंत्र का निर्माण शामिल है।
- ◆ इस परियोजना का उद्देश्य **कनार गाँव से राजधानी के 60 वार्डों को पेयजल आपूर्ति करना** है, जिससे अंततः देहरादून के 60 वार्डों को लाभ होगा।

साल वृक्ष

- **शोरिया रोबस्टा (Shorea robusta)** या साल वृक्ष, डिप्टेरोकार्पेसी परिवार का एक वृक्ष प्रजाति है।
- यह वृक्ष भारत, बांग्लादेश, नेपाल, तिब्बत और **हिमालयी क्षेत्रों** का मूल निवासी है।
- **विवरण**
 - ◆ यह 40 मीटर तक ऊँचा हो सकता है तथा इसके तने का व्यास 2 मीटर होता है।
 - ◆ पत्तियाँ 10-25 सेमी. लंबी और 5-15 सेमी. चौड़ी होती हैं।
 - ◆ आर्द्र क्षेत्रों में साल सदाबहार होता है; शुष्क क्षेत्रों में यह शुष्क ऋतु में पर्णपाती होता है, जिसके अधिकांश पत्ते फरवरी से अप्रैल तक गिर जाते हैं और अप्रैल तथा मई में पुनः पत्ते निकल आते हैं।
 - ◆ साल वृक्ष को मध्य प्रदेश, ओडिशा और झारखंड सहित उत्तरी भारत में **सखुआ** के नाम से भी जाना जाता है।
 - ◆ यह दो भारतीय राज्यों- **छत्तीसगढ़ और झारखंड** का राज्य वृक्ष है।
- **संस्कृति**
 - ◆ हिंदू परंपरा में **साल वृक्ष को पवित्र माना जाता है**। इसे भगवान विष्णु से भी जोड़ा जाता है।
 - ◆ इस वृक्ष का सामान्य नाम 'साल' शब्द 'शाला' से आया है, जिसका संस्कृत में अर्थ 'प्राचीर' होता है।
 - ◆ जैन धर्मावलंबियों का मानना है कि **24वें तीर्थंकर महावीर को साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी**।
 - ◆ बंगाल की कुछ संस्कृतियों में **सरना बूढ़ी की पूजा की जाती है, जो साल वृक्षों के पवित्र उपवनों से जुड़ी देवी है**।
 - ◆ बौद्ध परंपरा के अनुसार **शाक्य** की रानी **माया** ने दक्षिण नेपाल के लुंबिनी के एक बगीचे में **साल वृक्ष या अशोक वृक्ष की शाखा को पकड़ते हुए गौतम बुद्ध को जन्म दिया था**।
 - ◆ बौद्ध परंपरा के अनुसार, **बुद्ध की मृत्यु के समय वे साल वृक्षों के बीच विश्राम कर रहे थे**।



मानसून के दौरान 13 ग्लेशियल झीलों से उत्पन्न संकट

चर्चा में क्यों ?

उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन विभाग (USDMA) 13 ग्लेशियल झीलों का सुभेद्यता अध्ययन करने जा रहा है, जिनमें से पाँच “उच्च जोखिम वाले क्षेत्र (High Risk Zone)” में हैं।

- अध्ययन का उद्देश्य झील आउटबर्स्ट से हुई बाढ़ जैसी आपदाओं से बचाव में मदद करने के लिये डेटा प्रदान करना है।

मुख्य बिंदु:

- अधिकारियों के अनुसार, जलवायु परिवर्तन के कारण हिमालय के ग्लेशियर खतरे में हैं और यह सुनिश्चित करने के लिये निरंतर जाँच की आवश्यकता है कि कोई अप्रिय घटना न हो।
- 13 उच्च जोखिम वाली झीलें पिथौरागढ़ ज़िले में दारमा, लासरयांघाटी और कुटियांगटी घाटी तथा चमोली ज़िले में वसुधारा ताल झील है।
- इनका आकार 0.02 से 0.50 वर्ग किलोमीटर तक है और ये समुद्र तल से 4,000 मीटर से अधिक ऊँचाई पर स्थित हैं।
- मार्च 2024 में, राज्य सरकार ने इन हिमानी झीलों से जुड़े जोखिमों का आकलन करने के लिये दो विशेषज्ञ टीमों का गठन किया था
- टीमों में भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान, भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, रुड़की, उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र और वाडिया हिमालय भू-विज्ञान संस्थान के विशेषज्ञ शामिल थे।

ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (Glacial Lake Outburst Flood- GLOF)

- परिचय:
 - ◆ ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (हिमानी झील के फटने से होने वाली बाढ़ आपदा) एक प्रकार की भयावह बाढ़ है जो तब होती है जब हिमानी झील वाला बाँध टूट जाता है और बहुत बड़ी मात्रा में जल का आवेग होता है
 - ◆ इस प्रकार के बाढ़ की घटना आमतौर पर ग्लेशियरों के तेज़ी से पिघलने या भारी वर्षा अथवा पिघले हिम-जल के प्रवाह के कारण झील में अत्यधिक जल संग्रह के कारण होती है
 - फरवरी 2021 में उत्तराखंड के चमोली ज़िले में फ्लैश फ्लड की घटना हुई, जिसके बारे में संदेह है कि यह GLOF के कारण हुआ है।
- कारण:
 - ◆ ये बाढ़ कई कारकों से शुरू हो सकती है, जिसमें ग्लेशियर के आयतन में परिवर्तन, झील के जल स्तर में परिवर्तन और भूकंप शामिल हैं।
 - ◆ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के अनुसार, हिंदू कुश हिमालय के अधिकांश हिस्सों में जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियरों के खिसकने/स्खलन से कई नई ग्लेशियल झीलों का निर्माण हुआ है, जो GLOF का प्रमुख कारण हैं।

